



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150]
No. 150]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 1986/चैत्र 4, 1908
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 1986/CHAITRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1986

सा. का. नि. 532 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 126”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1986

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1986 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार 1 अप्रैल, 1985 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में—

(क) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (11) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, जो उन स्तम्भों में वर्णित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कार्यक्रमों पर पूँजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं भारत का संचित निधि पर भारित होंगी :

सारणी

राज्य	पुलिस	निम्नलिखित को ऊँचा उठाने के लिए				निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊँचा उठाने के लिए				
		शिक्षा	जेल	जनजाति	स्वास्थ्य	न्यायिक	जिला और राजस्व	खजाना और लेखा	प्रशिक्षण	विशेष समस्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आन्ध्र प्रदेश	180.94	299.20	171.26	147.25	110.72	147.52	90.38	15.25	29.41	..
असम	296.93	576.10	164.40	82.85	54.86	66.35	9.20	5.75	15.35	..
बिहार	630.12	968.80	254.53	353.05	159.93	178.80	33.24	9.75	46.22	..
हिमाचल प्रदेश	47.83	175.35	6.73	12.23	23.56	15.83	19.55	6.90	7.71	10.00
जम्मू और कश्मीर	447.70	174.18	145.85	..	33.50	35.39	24.78	7.22	14.27	49.60
केरल	136.09	..	22.46	6.15	31.26	77.22	12.74	9.75	30.51	..
मध्य प्रदेश	840.22	..	1282.95	482.20	36.58	46.95	73.65	14.50	38.00	200.00
मणिपुर	81.93	208.54	88.14	33.54	12.97	5.19	6.47	3.32	2.70	40.00
मेघालय	38.12	168.11	116.97	..	9.08	3.25	2.21	3.32	2.04	..
नागालैण्ड	0.42	61.23	156.11	..	7.35	4.84	7.47	3.97	4.12	..
उड़ीसा	276.21	398.30	77.68	414.20	49.21	31.87	79.25	8.75	16.11	..
पंजाब	200.00
राजस्थान	137.83	..	104.30	94.40	58.85	54.47	62.14	5.75	25.70	200.00
सिक्किम	46.92	..	0.75	1.90	5.84	1.10	0.64	3.00	2.00	10.00
त्रिपुरा	120.11	98.67	4.07	11.97	11.89	3.25	4.46	3.00	7.75	16.00
उत्तर-प्रदेश	1243.35	..	455.63	1.65	232.42	81.25	126.15	18.25	53.60	..
पश्चिमी-बंगाल	1293.77	775.90	337.28	94.20	75.81	73.05	40.50	6.75	25.34	..

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ, और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम 1 अप्रैल, 1986, 1987 और 1988 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर उन वर्षों के लेखाओं से प्रकटित ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर उपगत वास्तविक व्यय के विरुद्ध समायोजन के अधीन रहते हुए हैं।

(ख) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (6) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ जो 1 अप्रैल, 1984 को प्रारम्भ होने वाले वाले वित्तीय वर्ष में उपगत उन स्तम्भों में उल्लिखित सेक्टरों

और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे:

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए				
	न्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्व जिला और जनजाति प्रशासन	स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण और खजाना प्रशासन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिहार	..	32.11	..	22.00	..
जम्मू कश्मीर	..	72.97
केरल	2.56
मध्य प्रदेश	..	0.69	45.73	20.27	..
मेघालय	6.40	0.74	..
सिक्किम	..	1.20
तमिलनाडु	166.74
त्रिपुरा	0.10	1.10
उत्तर प्रदेश	14.88
पश्चिमी बंगाल	..	240.67

परन्तु यदि उस वर्ष के लेखाओं से प्रकटित किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार अधिक संवत् रकम का किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्षों में से किसी में संचित हो जाए।

(2) 1 अप्रैल, 1985 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उप-पैरा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी राज्य को संचित कोई राशि या राशियाँ उस राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी या होंगी, जो संविधान (राजस्व वितरण) आदेश 1985 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उक्त वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संचित हो।

जैल सिंह, राष्ट्रपति

[फा. 19(1) 86—वि. 1]

एस० रामय्या, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1986

G. S. R. 532 (E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 126”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1986

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1986.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1986, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:—

TABLE

For upgradation of standards relating to										
State	Police	Educa- tion	Jail	Tribal	Health	Judicial	District and revenue	Treasury and accounts	Training	Special problems
(Rupees in Lakhs)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Andhra Pradesh	180.94	299.20	171.26	147.25	110.72	147.52	90.38	15.25	29.41	..
Assam	296.93	576.10	164.40	82.85	54.86	66.35	9.20	5.75	15.35	..
Bihar	630.12	968.80	254.53	353.05	159.93	178.80	33.24	9.75	46.22	..
Himachal Pradesh	47.83	175.35	6.73	12.23	23.56	15.83	19.55	6.90	7.71	10.00
Jammu and Kashmir	447.70	174.18	145.85	..	33.50	35.39	24.78	7.22	14.27	49.60
Kerala	136.09	..	22.46	6.15	31.26	77.22	12.74	9.75	30.51	..
Madhya Pradesh	840.22	..	1282.95	482.20	36.98	46.95	73.65	14.50	38.00	200.00
Manipur	81.93	208.54	88.14	33.54	12.97	5.19	6.47	3.32	2.70	40.00
Meghalaya	38.12	168.11	116.97	..	9.08	3.25	2.21	3.32	2.04	..
Nagaland	0.42	61.23	156.11	..	7.35	4.84	7.47	3.97	4.12	..
Orissa	276.21	398.30	77.68	414.20	49.21	31.87	79.25	8.75	16.11	..
Punjab	200.00
Rajasthan	137.83	..	104.30	94.40	58.85	54.47	62.14	5.75	25.70	200.00
Sikkim	46.92	..	0.75	1.90	5.84	1.10	0.64	3.00	2.00	10.00
Tripura	120.11	98.67	4.07	11.97	11.89	3.25	4.46	3.00	7.75	16.00
Uttar Pradesh	1243.35	..	455.63	1.65	232.42	81.25	126.15	18.25	53.60	..
West Bengal	1293.77	775.90	337.28	94.20	75.81	73.05	40.50	6.75	25.34	..

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government:

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial years commencing on the 1st day of April, 1986, 1987 and 1988 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as revealed in the accounts of those years.

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes approved by the Central Government for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, incurred in the financial year commencing on the 1st day of April, 1984 :—

TABLE

For upgradation of standards relating to					
State	Judicial administration	Police administration	Jail administration	Revenue, District and Tribal administrations	Stamps, Registration and Treasury administrations
(Rupees in lakhs)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bihar	..	32.11	..	22.00	..
Jammu and Kashmir	..	72.97
Kerala	2.56

1	2	3	4	5	6
Madhya Pradesh	..	0.69	45.73	20.27	..
Meghalaya	6.40	0.74	..
Sikkim	..	1.20
Tamil Nadu	166.74
Tripura	0.10	1.10
Uttar Pradesh	14.88
West Bengal	..	240.67

Provided that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State in the financial year commencing on the 1st day of April, 1985 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1985.

ZAIL SINGH,
President.

[No. F. 19(1)/86-LI]
S. RAMAIAH, Secy.